



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

CE

315] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 1991/ज्येष्ठ 6, 1913  
315] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 1991/JYAISTHA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1991

का. आ. 356(अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के लिए  
शिक्षित मामले, अर्थात्, 21 मई, 1991 को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी  
हत्या की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के आर्च न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे. एस्. वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करती है।

2 आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा :—

- (क) क्या श्री राजीव गांधी की हत्या को टाला जा सकता था और क्या उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किसी व्यक्ति की ओर से इस संबंध में कोई चूक या झूटी की अवहेलना हुई थी ; और
- (ख) सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था में, जैसा कि विहित है या व्यवहार में प्रचलित है, कमियां, यदि कोई हों, जिनके कारण यह हत्या हुई है।

3. आयोग ऐसे सुधार-विषयक उपायों और उपचारों की सिफारिश भी कर सके जो उपरोक्त पैरा 2 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भविष्य में किए गए आवश्यक हैं।

4. आयोग अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र, किन्तु तीन मास के अंदर प्रस्तुत करेगा।

5. यदि आयोग ठीक समझे तो वह उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित विषयों में से कि भी विषय पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उक्त तारीख से पहले दे सकेगा।

6. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मा की अन्य परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और धारा (5) सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किये जाएं और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[सं. 1/12014/5/91 - आई. एस. (डी - II

आर. के. भागवत, गृह स.

---

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Dehli, the 27th May, 1991

S. O. 356(E).—WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the assassination of Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India on the 21st May, 1991;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Justice Shri J. S. Verma, a sitting Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

- (a) whether the assassination of Shri Rajiv Gandhi could have been averted and whether there were lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the individuals responsible for his security;
- (b) the deficiencies, if any, in the security system and arrangements as prescribed or operated in practice which might have contributed to the assassination.

3. The Commission may also recommend the corrective remedies and measures that need to be taken for the future with respect to the matters specified in clause (b) of paragraph 2 above.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months.

5. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2 above.

6. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

7. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. I/12014/5/91-IS(D. III)]

R. K. BHARGAVA, Home Secy.

